delays in rehabilitations, etc. of village and smaller tiny industries. The Committee also suggested a smooth exit policy for unviable sick units with a one-time settlement of suitably scaled down bank dues.

Central Fund for Small Scale Industries

2969. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 200 given in the Rajya Sabha on 9th July, 1992 and state:

(a) whether the Small Industry Modernisation Fund for Modernisation and Upgradation of Small Scale Sector has been set up; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

मारूति कारों की बिक्री

2970. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989–90, 1991–92, और 1992–93 की अवधि के दौरान कितनी मारूति कारों का विनिर्माण किया गया और बेचा गया ;

(ख) कारखानों से शोरूम ले जाते समय आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मारूति कारों की संख्या कितनी-कितनी है और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस हानि के लिये किन-किन व्यक्तियों को उत्तरदायी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विनिर्माण किए गए और बेचे गए मारूति वाहनों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :–

वर्ष	उत्पादन (संख्या)	बिक्री (संख्या)
1989–90	1,17,521	1,17,255
1990–91	1,23,083	1,20,302
1991–92	1,21,167	1,22,438
1992–93*	1,13,906	1,11,197
(28.2.93 तक)		

*अनन्तिम

(ख) और (ग) परिवहन के दौरान कारों का क्षतिग्रस्त होना प्रचालनों का एक सामान्य भाग है।

खादी आयोग द्वारा सरकार से स्वीकृति लिये बिना ही भूमि की खरीद

2971. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी आयोग और खादी भवन के प्रबन्धन को सरकार से स्वीकृति लिये बिना ही नोएडा में 90 लाख रुपये के मूल्य की भूमि अथवा दुकानें खरीदने का अधिकार प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग) के०बी०आई०सी० की भूमि खरीदने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है । नोएडा में के०वी०आई०सी० द्वारा भूमि की खरीद के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Norms for declaring district industrially backward

2972. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI MOHD. MASUD KHAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the norms laid down for declaring a district industrially backward;

(b) what is the number of districts in Rajasthan which have been declared industrially backward; and

(c) whether there is any proposal to declare Sawai Madhopur as an industrially backward district as per the norms of Government, if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMEN OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) The criteria adopted for identification of industrially backward districts were:

(i) Percapita food grains|commercial crops production depending on whether the district is predominantly a producer of food grains| cash crops. (for inter-district comparisons conversion rates between foodgrains and commercial crops may be determined by the State Government on a pre-determined basis where necessary).

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) per capita industrial output.

(iv) Number of factory employees per lakh of population or alternatively number of person engaged in secondary and tertiuary activities per lakh of population.

(v) per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surface roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

(b) The number of industrially backward districts identified by the Central Government for Rajasthan is sixteen.

(c) No, Sir. Government have decided that industrialisation of less industrialised areas would be through creation of infrastructural facilities under the Growth Centre Scheme announced in 1988.

गुजरात में लघु मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योग

2973. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किये गये लघु मध्यम और बड़े उद्योगों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या गुजरात राज्य की सरकार ने ऐसे उद्योग स्थापित किए जाने के लिए अपेक्षित बिजली और निधियां सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?